जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 65 प्रभात बीकानेर, शनिवार 27 सितम्बर, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

ट्रंप ने दवाओं के आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया, एक अक्टूबर से लागू होगा

ट्रंप के इस फैसले से भारतीय फार्मा उद्योग प्रभावित होंगे, जिनका 45 प्रतिशत बिज़नैस अमेरिका के साथ है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 सितंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं के आयात पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ (शुल्क) लगाया जाएगा। भारत की फार्मास्यूटिकल्स (दवा) इंडस्ट्री, जो अमेरिका के साथ व्यापार पर अत्यधिक निर्भर है, इस फैसले से गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।

ट्रंप ने "ट्रुथ सोशल' पर कहा, "1 अक्टूबर 2025 से, हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल उत्पाद पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे, जब तक कि संबंधित कंपनी अमेरिका में अपनी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण नहीं कर रही हो।

- ट्रंप ने घोषणा की है कि इस टैरिफ वृद्धि से उन फार्मा कंपनियों को राहत मिलेगी, जो अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग केन्द्र बनाने की तैयारी कर रही हैं।
- अमेरिका, भारत के फार्मा उद्योग का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल फार्मा एक्सपोर्ट का 31 प्रतिशत अमेरिका को हुआ था और इस वर्ष 2025 की पहली छमाही में 3.7 अरब डॉलर का फार्मा निर्यात हो चुका है।
- ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फैसले की जानकारी दी, साथ ही किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटीज़ और फर्नीचर पर भी टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की।
- ट्रंप टैरिफ वृद्धि का कोई वैध कारण नहीं बता सके, पर उन्होंने कहा, देश की सुरक्षा के लिए टैक्स वृद्धि जरुरी है।

ट्रंप की यह पोस्ट स्पष्ट करती है कि अगस्त में शुरु किए गए ट्रेड फ्रेमवर्क्स और आयात करों के बावजूद उनकी टैरिफ नीति जारी है। उनका मानना है कि इन टैक्सों से सरकार का बजट घाटा कम होगा और घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे स्पष्ट किया: "इज़ बिल्डिंग" की परिभाषा होगी, निर्माण कार्य शुरू करना या निर्माणाधीन होना। यदि निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, तो ऐसे फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर टैरिफ नहीं लगेगा। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।

ट्रंप की इस टैरिफ नीति के तहत अन्य उत्पादों पर भी शुल्क लगाया गया है, जैसे किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटीज़ पर 50 प्रतिशत शुल्क, तैयार फर्नीचर पर 30 प्रतिशत, भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत शुल्क, हालांकि ट्रंप ने इन टैरिफों के लिए कोई कानूनी आधार नहीं बताया, उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहा कि ये टैक्स "राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों" से आवश्यक हैं।

अमेरिका भारत के फार्मास्यूटिकल उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के कुल 27.9 बिलियन (लगभग 2.47 लाख करोड़) मूल्य के दवा निर्यात में से 31 प्रतिशत या 8.7 बिलियन डॉलर (77,138 करोड़) अमेरिका को भेजे गए थे। वहीं 2025 के पहले 6 महीनों में ही भारत ने अमेरिका को 3.7 बिलियन डॉलर (32,505 करोड़) के फार्मा उत्पाद भेजे हैं

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका में उपयोग होने वाली 45 प्रतिशत से अधिक जैनरिक और 15 प्रतिशत बायोसिमिलर दवाएं भारत से भेजी जाती हैं। रेड्डीज़, ऑरबिंदो फार्मा, ज़ायडस लाइफसाइंसेज, सन फार्मा और ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनियां अपनी कुल आय का 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अमेरिकी बाजार से कमाती हैं। हालांकि नई अमेरिकी टैरिफ नीति मुख्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए गए ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं को लक्ष्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जस्टिस एस.पी. शर्मा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने

जयपुर, 26 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया कि 27 सितंबर को मौजूदा सीजे केआर श्रीराम के सेवानिवृत्त होने के कारण जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

- जस्टिस शर्मा का रिटायरमैंट 26 सितंबर 2026 को होगा।

जस्टिस एसपी शर्मा का जन्म 27 सितंबर, 1964 को हुआ था। एलएलबी करने के बाद उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत करना आरंभ किया। उन्हें 16 नवंबर, 2016 को हाईकोर्ट में वकील कोटे से न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद जनवरी, 2022 में पटना हाईकोर्ट में उनका तबादला किया गया। जहां से इन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भेजा गया। इसके बाद गत 14 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला किया गया था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दशकों से अमेरिका आयातित "ड्रग्स" पर निर्भर है

इस निर्भरता का रातों-रात अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं विकसित किया जा सकता

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 सितंबर। जैसा कि पहले से चेतावनी दे रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने कुछ चुनिंदा उत्पादों पर नया टैरिफ (आयात शुल्क) लगा दिया है। इस बार के टैरिफ पहले के मुकाबले अलग हैं, क्योंकि ये खास उद्योगों पर केन्द्रित हैं।

ट्रम्प ने दवाओं, ट्रकों, किचन कैबिनेट्स और फ़र्नीचर पर टैरिफ लगाया है। इनमें से दवाओं के आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ भारत के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका को दवाओं का प्रमुख निर्यातक है। यह कदम अमेरिका के लिए भी उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि टैरिफ के कारण दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।

उद्योग संघों और व्यापार संगठनों को डर है कि एक अक्टूबर से लागू होने वाले इन नए टैरिफ के कारण मरीजों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका लंबे समय से दवाओं और अन्य मैडिकल केयर उत्पादों के आयात पर निर्भर रहा है। अब रातों-रात घरेलू उत्पादन इनकी जगह नहीं ले सकते।

ट्रम्प ने नए टैरिफ को भविष्य की निवेश योजनाओं से जोड़कर तय किया है। जो कंपनियाँ अमेरिका में बड़े निवेश की योजना बनाएँगी, उन्हें कम या बिल्कुल टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। इन निर्णय का सीधा मकसद कंपनियों को अपने पुराने देशों से निकलकर अमेरिका में आकर निवेश करने के लिए लुभाने का प्रयास है

- इसीलिए, ट्रंप द्वारा फार्मास्युटिकल्स पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा में कई "रास्ते" (लूप होल्स) छोड़े गये हैं। उदाहरण के लिए, जो फार्मास्युटिकल कंपनी अमेरिका में अपनी "प्रोडक्शन यूनिट" लगाने का प्रस्ताव रखती है, उन पर टैरिफ कम लगेगा।
- साथ ही, 100 प्रतिशत टैरिफ सभी "जैनरिक दवाइयों" (मूल दवा) पर नहीं लगेगा, बल्कि फार्मास्युटिकल कंपनी के "पेटेन्टैड प्रोडक्ट्स" पर ही लगेगा।
- विदेशी कंपनियों को अमेरिका में प्रोडक्ट्स की सुविधा लगाने की नीति का यूरोप व इंगलैंड पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जानी मानी ड्रग्स कंपनी ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन बीचम सालों से इंगलैंड में जमी हुई थी, पर वह अपना एक्सपैंशन इंगलैंड में नहीं, बल्कि अमेरिका में शिफ्ट कर रही है।
- इसी प्रकार किचन कैबिनेट आदि फर्नीचर के पुराने व प्रतिष्ठित निर्माता, स्वीडन की कंपनियों को भारी नुकसान की आशंका है, क्योंकि अमेरिका उनके लिए बड़ा, शायद सबसे बड़ा ग्राहक है।

पूर्व में ऐसे तरीकों को प्रमुख पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएँ, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, अनुचित और अस्वीकार्य मानती थीं। अब वही अमेरिका इस तरह की भेदभावपूर्ण नीतियों को खुले तौर पर अपना रहा है।

दवाओं पर यह टैरिफ भारत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाएँ और ऐसा कच्चा माल भी भेजता है, जिससे अन्य दवाएँ तैयार होती हैं।

हालाँकि थोड़ी राहत यह है कि टैरिफ का दायरा कुछ सीमित रखा गया है। यह टैरिफ विशुद्ध रूप से जेनेरिक दवाओं और उनके कच्चे माल पर लागू नहीं है। इससे मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों की ब्रांडेड दवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका में दवा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित निवेश के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रॉनल्ड रीगन के फॉर्मूले को दोहरा रहे हैं मोदी

पूर्व राष्ट्रपति रॉनल्ड रीगन ने सेल्स टैक्स में भारी कटौती कर जनता को काफी रकम उपलब्ध कराई, खर्चा करने के लिए

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 सितंबर। सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह जनता के हित में काम कर रही है और लाभ लोगों को दे रही है। यही सरकार पहले ही आयकर में 12 लाख रुपये सालाना तक की छूट देकर जनता को बड़ा तोहफ़ा दे चुकी है। इन दोनों रियायतें को मिलाकर लोगों के हाथों में लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपये बचेंगे और यह लाभ त्योहार के इस सीज़न में उनकी खरीददारी की क्षमता बढ़ाएगा। यह कोई नया आर्थिक प्रयोग नहीं, बल्कि जानी मानी आर्थिक रणनीति है, जिसे पहले भी कई बार आज़माया जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति रॉनल्ड रीगन ने बड़े पैमाने पर टैक्स कटौती की थी और उम्मीद की थी कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहने से मांग बढ़ेगी और पूरी अर्थव्यवस्था में निवेश व उत्पादन का चक्र तेज़ होगा। यह प्रयोग अमेरिका में सफल रहा और मांग, उत्पादन और निवेश का सकारात्मक चक्र बना।

- इससे उस समय अमेरिका में "डिमांड" में भारी वृद्धि हुई, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा और इन्वैस्टमैंट बढ़ा इण्डस्ट्री में।
- मोदी ने भी 12 लाख करोड़ रूपए की आय को इनकम टैक्स फ्री करके जनता के हाथ में पैसा दिया तथा जीएसटी भी कम किया, जिससे रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों की कीमत भी काफी घटी।
- इसके साथ, अमेरिका द्वारा खड़ी की गई टैरिफ की दीवार के कारण, अमेरिका के मार्केट के लिए बनी वस्तुएं आगे नहीं खिसक रही थीं तथा कारखानों के गोदामों में फिनिश्ड गुड्स भरे हुए थे। अतः कंपनियों को भारी मदद मिली, अपने रूके हुए सामान से भारत के डॉमेस्टिक बाज़ार की "डिमांड" पूरी करने में।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मनमोहन सिंह के नाम पर कांग्रेस मुख्यालय में पुस्तकालय खुला

नयी दिल्ली, 26 सितबर। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी तथा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को यहां पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नाम पर अनुसंधान केन्द्र और पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इसका नाम डॉ. मनमोहन सिंह अनुसंधान केन्द्र और पुस्तकालय रखा गया है। यह केन्द्र कांग्रेस के नये मुख्यालय इंदिरा भवन में स्थापित किया गया है। इस केन्द्र पर डॉ. सिंह की पुस्तकें, उनके लेख और भाषणों के संकलन रखे गये हैं।

- सोनिया गांधी और खड़गे ने अनुसंधान केन्द्र व पुस्तकालय का उद्घाटन किया।

इस मौके पर डॉ. सिंह की पत्नी गुरशरण कौर, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तान ने फिर दोहराया, ट्रंप ने रूकवाया था भारत-पाक युद्ध

पाक प्र.मंत्री शहबाज़ शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा पर जारी अधिकृत बयान में पाकिस्तान ने ट्रंप के दावे का समर्थन किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 सितम्बर। क्या पाकिस्तान ने यह स्वीकार कर लिया है कि अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ संघर्षविराम सुनिश्चित करने में उसकी मदद की थी? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत के विवरण से संकेत मिलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने संघर्षविराम शुरू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत ने कई बार इन दावों का खंडन किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उस संघर्षविराम में कोई भूमिका निभाई थी, जो अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले (जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे) के बाद, पाकिस्तान में आतंकी और सैन्य ढांचे पर की गई एयरस्ट्राइक्स के बाद लागू हुआ था।

- पाकिस्तानी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत-पाक सीज़फायर करवाने के लिए ट्रंप के साहसिक व निर्णायक नेतृत्व की प्रशंसा की। यह बात एक तरह से पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति है कि ट्रंप ने सीज़फायर करवाया था।
- हालांकि, भारत ने बार-बार कहा है कि सीज़फायर में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। भारत ने कहा कि 22 अप्रैल (पहलगाम) अटैक से लेकर 17 जून (सीज़फायर घोषणा) तक ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर कोई बात नहीं हुई थी।

लेकिन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान के नेताओं की तरह ही दावा किया है कि वे भी एक कारण रहे थे, जिसकी वजह से दोनों परमाणु-शक्ति संपन्न पड़ोसी देश संघर्षविराम पर सहमत हुए और तनाव को बढ़ने से रोका गया। पाकिस्तानी बयान में कहा गया: "प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज़ शरीफ़ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान-भारत संघर्षविराम को सुविधाजनक बनाने में राष्ट्रपति ट्रंप के साहसिक, निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की और गाज़ा में संघर्ष को तुरंत समाप्त करने तथा मध्य पूर्व में शांति बहाल करने के प्रयासों के तहत, मुस्लिम जगत के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित करने की उनकी पहल की प्रशंसा की।"

बयान में आगे कहा गया: "नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की, जिसमें प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को आमंत्रित किया और सुरक्षा तथा खुफिया सहयोग को और बढ़ाने की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जस्टिस सौमेन सेन मेघायलय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

नयी दिल्ली, 26 सितबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मु ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।

- वे वर्तमान में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं।

केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई।

अधिसूचना में कहा गया है, "राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।"

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना काम काज "ऑफिस सुईट ज़ोहो" पर शिफ्ट किया

जैसा कि विदित ही है, ज़ोहो कॉर्पोरेशन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिक है, जो कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और वैब आधारित बिज़नेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह अपील कि भारतीय लोग "स्वदेशी टैक" को अपनाएँ, तकनीक में आत्मनिर्भरता की बहस को दोबारा तेज कर रही है। आत्मनिर्भर भारत की बड़ी सोच के हिस्से के रूप में पेश की गई यह पहल विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करने और भारत को नवाचार का वैश्विक केन्द्र बनाने का लक्ष्य रखती है।

स्वदेशी टैक का यह प्रयोग पूरे देश में एक जन आंदोलन बनेगा या सिर्फ प्रतीकात्मक कदम रह जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चुनौतियों को कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से निपटाया जाता है। केवल नीतिगत मदद, नवाचार और बाज़ार में स्वीकार्यता का मेल ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि स्वदेशी टैक भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का ठोस आधार बने।

सरकार ने इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत कदमों के साथ प्रतीकात्मक काम भी किए हैं। केन्द्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का भारतीय ऑफिस सॉफ़्टवेयर सूट ज़ोहो का उपयोग शुरु करना घरेलू विकल्पों को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण मिसाल है। अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ की राष्ट्रीय मुहिम मोदी की अपील को जन आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रही है। इसी बीच, मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) जैसी योजनाएँ स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को घरेलू तकनीकी समाधान विकसित करने और बढ़ाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और इन्फ्रस्ट्रक्चर सम्बंधी मदद दे रही हैं।

- भारत सरकार की विदेशी, अमेरिकी आदि कंपनियों पर निर्भरता कम करने की दृष्टि से "स्वदेशी टैक्नॉलजी को देश में पनपाने की मुहिम ही शायद एक रास्ता है, विदेशी सरकारों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल से मुक्त होने का।
- पर, इस मुहिम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि भारत की जनता इन स्वदेशी टैक्नॉलजी वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स को कितनी जल्दी और तत्परता से अपनाती है।
- "स्वदेशी टैक" को भी जनता तभी स्वीकार करेगी, जब ये प्रोडक्ट्स, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले कमज़ोर साबित न हों।
- ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए, लगातार आर. एण्ड डी. पर भारी खर्च करना होगा तथा भारतीय कामगारों में "स्किल" (हुनर) भी किसी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में पोचा न पड़े तथा सरकार की नीतियों का पूर्ण सहयोग व प्रोत्साहन मिले इस "स्वदेशी टैक" को।

भारत के पास स्वदेशी टैक के सपने को पूरा करने की मजबूत नींव मौजूद है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज की

प्रयागराज, 26 सितंबर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिख समुदाय से जुड़े विवादित बयान को लेकर दायर निगरानी याचिका के खिलाफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश समीर जैन की अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद तीन सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिस पर

- राहुल गांधी ने सिख सम्बंधी विवादित बयान पर एमपी-एमएलए कोर्ट में निगरानी याचिका स्वीकार किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)